

जो मनुष्य सब को खुश रखना चाहता है, वह किसी को खुश नहीं करेगा। -महात्मा गांधी-

वर्ष- 19	अंक- 180	जयपुर. बुधवार .	28 अक्टूबर , 2026	RNI No. RAJHIIN/2008/26744	मूल्य 1 रूपया	पृष्ठ - 4
----------	----------	-----------------	-------------------	----------------------------	---------------	-----------

न्यूज इनबॉक्स

अभिषेक-वैभव की आंधी में उड़ा न्यूजीलैंड, रिकॉर्ड्स की लगी झड़ी

वेलिंगटन (एजेंसी) । भारत और न्यूजीलैंड के बीच वेलिंगटन में जारी पांच मैचों की टी20 सीरीज के तीसरे मैच में टीम इंडिया ने रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने 20 ओवर में 3 विकेट पर 198 रन बनाए थे। जवाब में भारत ने बैटिंग ऑर्डर में बदलाव किया और अभिषेक शर्मा के साथ वैभव सूर्यवंशी को ओपनिंग के लिए भेजा। इसके बाद इन दोनों ने रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी। पावरप्ले में सबसे बड़े स्कोर से लेकर सबसे तेज 100 रन पूरे करने का रिकॉर्ड भारत ने तोड़ दिया है। हालांकि, अभिषेक शर्मा अपने गुरु युवराज सिंह का सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड तोड़ने से चूक गए। इतना ही नहीं, अभिषेक सबसे तेज शतक टी20 अंतरराष्ट्रीय शतक का अपना रिकॉर्ड तोड़ने से चूक गए। उन्होंने 38 गेंद में 9 चौके और 11 छक्के की मदद से 113 रन की पारी खेली। इसके अलावा वैभव ने 19 गेंद में चार चौके और चार छक्के की मदद से 45 रन की पारी खेली। भारत ने तीसरा टी20 छह विकेट से अपने नाम किया। 199 रन का लक्ष्य भारत ने 13.2 ओवर में हासिल कर लिया।

भारत के लिए टी20 अंतरराष्ट्रीय की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के

अभिषेक शर्मा ने अपनी 113 रन की पारी में 11 छक्के लगाकर भारत के लिए टी20 अंतरराष्ट्रीय की एक पारी में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में दूसरा स्थान हासिल किया। वह इस सूची में खुद के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ मुंबई में 13 छक्के लगाए थे, जो भारतीय बल्लेबाज का रिकॉर्ड है। अफगानिस्तान के खिलाफ दिल्ली में 2026 में भी उन्होंने 11 छक्के लगाए थे।

टी20 अंतरराष्ट्रीय की एक पारी में 10 या उससे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड

अभिषेक शर्मा टी20 अंतरराष्ट्रीय में एक पारी के दौरान 10 या उससे अधिक छक्के लगाने के मामले में भी लगातार अपना प्रभाव छोड़ रहे हैं। वेलिंगटन में 11 छक्कों के साथ उन्होंने इस सूची में अपनी तीसरी ऐसी पारी दर्ज की। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, इस मामले में ऑस्ट्रेिया के करनबीर सिंह पांच पारियों के साथ शीर्ष पर हैं। अभिषेक तीन बार यह कारनामा कर चुके हैं।

कुल टी20 क्रिकेट में एक पारी में 10 या उससे ज्यादा छक्के

कुल टी20 क्रिकेट में भी अभिषेक शर्मा का नाम बड़े हिट लगाने वाले बल्लेबाजों में शामिल है। वेलिंगटन की पारी के साथ वह टी20 क्रिकेट में 10 या उससे अधिक छक्के लगाने के मामले में सात बार ऐसा कर चुके हैं। इस सूची में वेस्टइंडीज के क्रिस गेल 18 पारियों के साथ शीर्ष पर हैं, जबकि वैभव सूर्यवंशी और करनबीर सिंह पांच-पांच बार यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं।

कर्नाटक में फाइनल वोटर लिस्ट जारी

एसआईआर के बाद लगभग 1 करोड़ मतदाता हुए कम

बेंगलुरु (एजेंसी) । कर्नाटक में ‘स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन’ (एसआईआर) 27 अक्टूबर को पूरा हुआ। इसके चलते राज्य के मूल 5.5 करोड़ मतदाताओं की सूची से लगभग 99.76 लाख मतदाता कम हो गए हैं, जिससे अब कुल मतदाताओं की संख्या 4,54,55,689 यानी 4.54 रह गई है। इनमें से लगभग 86.56 लाख मतदाता 20-29 आयु वर्ग के हैं, जबकि नए मतदाताओं की संख्या 6.83 लाख है। 16 जून को, जब एसआईआर प्रक्रिया के लिए मतदाता सूची के प्रीज कर किया गया था, तब राज्य में लगभग 5.5 करोड़ मतदाता थे। इसके बाद हुई जांच प्रक्रिया के दौरान, 24 अगस्त को जारी ड्राफ्ट सूची में लगभग 19.48 प्रतिशत यानी 1.08 करोड़ मतदाताओं को हटा दिया गया। इन्हें एसएडीडीओ यानी अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत, डुप्लिकेट और अन्य श्रेणी में रखा गया था। ड्राफ्ट सूची से हटाए गए मतदाताओं में सबसे बड़ा हिस्सा उन लोगों का था जिन्हें स्थायी रूप से स्थानांतरित माना गया। इस श्रेणी में 65.45 लाख मतदाता शामिल रहे, जो एसएडीडीओ लिस्ट का 11.8 प्रतिशत हिस्सा है।

नोटिस चरण के बाद, अंतिम सूची में शामिल होने वाले लोगों की संख्या 43.82 लाख में से 43.2 लाख रही, जबकि नोटिस के बाद 61,867 मतदाताओं की संख्या सूची से बाहर कर दिया गया। राज्य में 30 से 39 साल की आयु वाले मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक है, वर्तमान में 4.5 करोड़ मतदाताओं में से 1.02 करोड़ इसी आयु वर्ग के हैं। कर्नाटक में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं की तुलना में चार लाख अधिक है। 24 अगस्त से शुरू हुए दो महीने के दावे नोटिस और आपत्तियों के चरण में, ड्राफ्ट सूची में शामिल 4.4 करोड़ मतदाताओं में से लगभग 43.8 लाख लोगों ने नोटिस जारी किए गए। अधिकारियों ने बताया कि इनमें से लगभग 60,000 लोगों को अंतिम सूची से हटा दिया गया।



घटते जलस्रोत, बढ़ती आबादी और पानी की बर्बादी ने बढ़ाई मुश्किलें

देश में पेयजल संकट अभी से गहराने लगा है, जबकि अभी मानसून की विदाई हुई है। महाराष्ट्र में राज्य सरकार ने 16 अक्टूबर से सभी शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों में कम से कम 10 प्रतिशत जल कटौती लागू करने का निर्णय लिया है। राज्य के जालना जिले में बांध में केवल 2 प्रतिशत पानी बचा है। नौबत यहां तक आ गई है कि प्रशासन को पानी की चोरी रोकने के लिए पुलिस और राजस्व विभाग की टीमों के साथ रात में भी निगरानी और गश्त करनी पड़ रही है। इस बार मानसून में बारिश की करीब 12–13 प्रतिशत की कमी के कारण देश के दूसरे राज्यों की हालत भी महाराष्ट्र जैसी होने से इंकार नहीं किया जा सकता। देश के कई राज्यों में कम बारिश का असर अब जलाशयों पर दिख रहा है। 1 अक्टूबर तक देश के प्रमुख जलाशयों में 71.84 फीसदी पानी था। पिछले साल इसी समय यह 90.31 फीसदी था, जबकि सामान्य स्तर 81.79 फीसदी है। अर्थात इस बार जलाशयों में पानी पिछले साल के मुकाबले काफी कम है। देशभर में इस बार का मानसून 13वां सबसे सूखा सीजन रहा। पिछले 11 सालों में यह सबसे कम बारिश वाला मानसून रहा है। हालांकि सीजन खत्म होने से पहले हुई तेज बारिश के कारण बारिश की कमी में 2.5 फीसदी का सुधार हुआ। मानसून-2026 सीजन सामान्य से 12.6 फीसदी कम बारिश के साथ खत्म हुआ। देश के 43 फीसदी जिलों में 20 से 72 फीसदी तक कम बारिश हुई। सबसे ज्यादा पंजाब में 41 फीसदी कम बारिश हुई। राजस्थान में करीब 22 फीसदी कमी दर्ज की गई। इनके अलावा 9 राज्यों में भी औसत से कम बारिश हुई।

पूर्वी भारत में ओडिशा में सामान्य से 30 फीसदी ज्यादा बारिश हुई, जबकि बारिश के लिए प्रसिद्ध पूर्वांचल राज्यों में इस साल 1901 के बाद सबसे कम बारिश दर्ज की गई। पानी की कमी का असर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, राजस्थान और तमिलनाडु में ज्यादा दिख रहा है। कई इलाकों में खेती के लिए पानी कम पड़ रहा है और फसलों को भी नुकसान हो रहा है। आजादी के साठ वर्षों के बाद भी देश की एक-तिहाई जनता को पीने के लिए स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं है। शायद यही कारण है कि प्रतिवर्ष जलजनित बीमारियों के चलते 15 लाख बच्चे काल के गाल में समा जाते हैं और काम के अनगिनत घंटों का नुकसान होता है। समस्या यह है कि केंद्र एवं राज्य सरकारें पेयजल संकट को दूर करने के लिए गंभीर नहीं, जबकि वे इससे परिचित हैं कि आने वाले समय में पानी के लिए युद्ध छिड़ सकते हैं। भारत में पेयजल संकट बढ़ती आबादी और कृषि की जरूरतों के कारण भी गंभीर होता जा रहा है। करीब 65–70 प्रतिशत जल कृषि कार्यों में खप जाता है। इसके अतिरिक्त उद्योगों के संचालन में भी जल का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। विर्डबना यह है कि न तो उद्योग एवं कृषि क्षेत्र को अपनी आवश्यकता भर पानी उपलब्ध हो पा रहा है और न ही आम आदमी को। हमारे देश में जल संकट जब-तब गंभीर रूप ले लेता है। बात चाहे कावेरी जल विवाद के कारण तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच की तनातनी की हो अथवा यमुना जल के बंटवारे को लेकर दिल्ली एवं हरियाणा के बीच की, ऐसे विवाद लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब तो जल बंटवारे को लेकर राजनीति भी होने लगी है और एक प्रांत के लोगों को दूसरे प्रांत के लोगों के समक्ष खड़ा करने में संकोच नहीं किया जा रहा है। इन दिनों होंगकाल पेयजल परियोजना को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच यही हो रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार देश के 60 करोड़ लोग पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं, जबकि 16 करोड़ लोग गंदा पानी पी रहे हैं। शुद्ध पानी के लिए सरकार करोड़ों-अरबों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं।

देश के करीब 9 राज्यों में पानी की गुणवत्ता खराब है। नीति आयोग की कंपोजिट वॉटर मैनेजमेंट इंडेक्स रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में पानी की वजह से हर साल दो लाख लोगों की मौत हो रही है। साल 2030 तक यह स्थिति और विकराल हो जाएगी जब देश की लगभग 40 फीसदी आबादी के सामने पानी का संकट होगा। विकसित भारत के 2047 के लक्ष्य तक देश में पेयजल की हालत का तो आकलन ही नहीं किया गया है। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे के वैश्विक स्तर पर कुल पानी की सालाना निकासी या खपत के मामले में भारत पहले पायदान नंबर-1 पर है। अत्यधिक आबादी और कृषि (सिंचाई) के कारण सबसे आगे है। वैश्विक जल गुणवत्ता सूचकांक में भारत 122 देशों में से 120वें स्थान पर है। सुरक्षित पेयजल और जल गुणवत्ता के मामले में भारत की गिनती दुनिया के सबसे निचले स्तर के देशों में होती है।

पेयजल से लेकर जल संरक्षण की योजनाओं पर अत्यंत शिथिलता बरती जा रही है। दो वर्ष पूर्व आम बजट में ऐसी योजनाओं के लिए तमाम प्रावधान किए गए थे, लेकिन इस बजट में वे सिर से गायब हैं। देश को विकसित राष्ट्र बनाने में जल संसाधन का उत्तना ही महत्व है जितना ऊर्जा और अन्य साधनों का। जब तक ऐसी बुनियादी सुविधाओं का समाधान नहीं होगा, तब तक विकसित राष्ट्र का सपना एक छलावा ही साबित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम को एक घंटे तक संबोधित करते हुए कहा कि जब तक भारत विकसित नहीं होता, तब तक न धकूंगा, न रुकूंगा। इस नारे का 19 बार जिक्र किया।

पेयजल से लेकर जल संरक्षण की योजनाओं पर अत्यंत शिथिलता बरती जा रही है। दो वर्ष पूर्व आम बजट में ऐसी योजनाओं के लिए तमाम प्रावधान किए गए थे, लेकिन इस बजट में वे सिर से गायब हैं। देश को विकसित राष्ट्र बनाने में जल संसाधन का उत्तना ही महत्व है जितना ऊर्जा और अन्य साधनों का। जब तक ऐसी बुनियादी सुविधाओं का समाधान नहीं होगा, तब तक विकसित राष्ट्र का सपना एक छलावा ही साबित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम को एक घंटे तक संबोधित करते हुए कहा कि जब तक भारत विकसित नहीं होता, तब तक न धकूंगा, न रुकूंगा। इस नारे का 19 बार जिक्र किया।

91000 करोड़ रुपये लागत की संशोधित पार्वती कालीसिंध चम्बल लिंक परियोजना में 23312 करोड़ रुपये के 7 पेयजल कार्य प्रगति पर**प्रथम पैकेज पर अब तक 1,006 करोड़ रुपये खर्च**

जयपुर (कासं)। दौसा और सवाई माधोपुर जिले के समग्र विकास में सबसे बड़ी बाधा पानी की कमी रही है। अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विकसित राजस्थानञ्च2047 का संकल्प पूरा करने में जल का महत्व समझते हुए इन दो जिलों के साथ ही सम्पूर्ण राज्य में पानी की समस्या के स्थायी समाधान के लिए संशोधित पार्वती कालीसिंध चम्बल लिंक परियोजना, किशौड बहुउद्देशीय बांध परियोजना, यमुना जल समझौते, देवास के अगले चरणों आदि के माध्यम से बड़े कदम उठाए, बरसों से लम्बित अन्तर्राज्यीय विवादों का समाधान किया और घोषणाओं के समय ही पूरे बजट का इंजाजाम भी किया जिससे घोषणाएं डेडलाइन पर नहीं, उससे पहले ही धरातल पर विकास की गंगा ला सके। डबल इंजन सरकार 91000 करोड़ रुपये की संशोधित पार्वती कालीसिंध चम्बल लिंक परियोजना

प्रदेश में बेहतर रोड कनेक्टिविटी से विकास को मिली नई रफ्तार: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सड़क निर्माण में अहम उपलब्धि

37,527 करोड़ रुपये से हुआ 51,790 किमी सड़कों का विकास, 9,704 करोड़ रुपये से बिछाई गई 18,917 किमी लंबाई की नई सड़कें, 1,760 गांव डामर सड़कों से जुड़े, 12,311 करोड़ रुपये से अधिक व्यय, अटल प्रगति पथों से ग्रामीण आबादी को मिल रहा सुगम आवागमन

जयपुर (कासं)। प्रदेश में गांवों से लेकर शहरों तक आमजन को सुगम आवागमन देने और आर्थिक गतिविधियों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी के दृष्टिकोण के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार सड़क विकास पर प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इसी का परिणाम है कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 37 हजार 527 करोड़ रुपये से अधिक व्यय कर 51 हजार 790 किलोमीटर लम्बी सड़कों का विकास किया गया है, जो प्रदेश में सड़क सम्पर्क के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

प्रधानमंत्री के विजन को साकार कर रहे मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुसार विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए देश-प्रदेश में बेहतर सड़क सम्पर्क आवश्यक है। इस दिशा में तेजी से कार्य करते हुए वर्तमान सरकार ने कुल 18 हजार 917 किलोमीटर लंबाई की चूई सड़कों के निर्माण पर 9 हजार 704 करोड़ रुपये से अधिक व्यय किए हैं।

वहीं, राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए 603 किलोमीटर लंबाई के कार्यों पर 4 हजार 210 करोड़ रुपये, राज्य राजमार्गों एवं मुख्य जिला सड़कों के विकास के लिए 8 हजार 318 किलोमीटर लंबाई के कार्यों पर 11 हजार 302 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं। मुख्यमंत्री द्वारा सितम्बर-अक्टूबर, 2026 के दौरान सभी 41 जिलों में सार्वजनिक निर्माण विभाग के 3 हजार 40 करोड़ रुपये की लागत वाले 1 हजार 763 कार्यों का शिलान्यास किया जा चुका है। वहीं, 371 करोड़ रुपये की लागत वाले 261 कार्यों का लोकार्पण भी किया गया है। इन विकास कार्यों से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में सड़क एवं आधारभूत संरचना को मजबूती मिलेगी और आमजन को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

विकास की मुख्य धारा से जुड़ रहे अंतिम छोर के गांव

राज्य सरकार द्वारा सभी ग्रामीण क्षेत्रों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने और आधारभूत सुविधाओं के विस्तार पर विशेष फोकस किया जा रहा है। सरकार द्वारा ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए 23 हजार 952

किलोमीटर लंबाई के कार्यों पर 12 हजार 311 करोड़ रुपये से अधिक व्यय किए गए हैं। इसके तहत 1 हजार 760 गांवों एवं 21 बसावटों को डामर सड़कों से जोड़ा गया है। इससे ग्रामीण आबादी को सुगम आवागमन के साथ ही कृषि, व्यापार और अन्य आर्थिक गतिविधियों में भी सुविधा मिल रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में धूल, कीचड़ और जलभराव की समस्याओं से राहत दिलाने के लिए अटल प्रगति पथ योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। इसके तहत 5 हजार से अधिक आबादी वाले गांवों में 765 अटल प्रगति पथों के निर्माण के लिए 1 हजार 686 करोड़ रुपये की स्वीकृतियां जारी की जा चुकी हैं। इनमें से 335 अटल प्रगति पथों का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि, शेष कार्यो को 31 जनवरी, 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

नॉन-पेचेबल और मिसिंग लिंक सड़क निर्माण की बढ़ी गति
राज्य सरकार द्वारा नॉन-पेचेबल सड़कों के नवीनीकरण तथा नए मिसिंग लिंक सड़क निर्माण के लिए वर्ष 2026–27 में 3 हजार 453

कार्यों हेतु 2 हजार 226 करोड़ रुपये की स्वीकृतियां जारी की जा चुकी हैं। इनमें से 2 हजार 836 कार्यों के कार्यादेश जारी कर 6 हजार 815 किलोमीटर सड़कों का नवीनीकरण एवं नया निर्माण किया जा रहा है। वहीं, वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त पुलियाओं की मरम्मत के लिए भी व्यापक कदम उठाए गए हैं। इसके तहत 21 जिलों के 73 विधानसभा क्षेत्रों में 58 करोड़ रुपये की लागत के 424 निर्माण कार्य जल्द शुरू किए जाएंगे।

आरओबी, आरयूबी और ऐलिवेटेड रोड से कम हुआ यातायात का दबाव

प्रदेश में सड़क नेटवर्क को अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए पुलों एवं रेलवे क्रॉसिंग पर आधारभूत संरचनाओं का विकास भी किया जा रहा है। राज्य में 13 रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) और 17 रेलवे अंडरब्रिज (आरयूबी) का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है, जबकि 39 आरओबी और 12 आरयूबी के कार्य प्रगतिरत हैं। इसके अलावा 13 उच्च स्तरीय पुलों का निर्माण पूरा किया जा चुका है और 13 का

निर्माण कार्य जारी है। इसी प्रकार भरतपुर शहर में हीरादास चौराहे से कुम्हर गेट चौराहे तथा काली बगीची चौराहे से बिजलीघर चौराहे होते हुए आरबीएम अस्पताल तक और जयपुर के सांगानेर क्षेत्र में मुहाना मोड़ पर एलिवेटेड रोड का निर्माण कार्य भी जारी है।

राष्ट्रीय राजमार्गों का हो रहा चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण

राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण की दिशा में 1 हजार 900 करोड़ रुपये व्यय कर 610 किलोमीटर लंबाई के 26 कार्य पूरे किए जा चुके हैं। जबकि 3 हजार 220 करोड़ रुपये की लागत से 303 किलोमीटर लंबाई के 26 कार्य प्रगतिरत हैं। वार्षिक योजना 2026–27 के अनुसार 12 हजार 461 करोड़ रुपये की लागत से राष्ट्रीय राजमार्गों के 623 किलोमीटर के कार्य का अनुमोदन किया गया है। इसमें से 3 हजार 920 करोड़ रुपये की लागत से190 किलोमीटर लम्बाई के 4 कार्यों की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

आधुनिक तकनीक से क्वालिटी की मॉनिटरिंग
राज्य सरकार पुख्ता मॉनिटरिंग

के जरिए सड़क निर्माण की क्वालिटी पर भी पूर्ण ध्यान दे रही है। इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से सीसीटीवी कैमरों, सेंसर और अन्य उपकरणों की मदद से यातायात की वास्तविक समय में निगरानी एवं प्रबंधन किया जा रहा है।

इसी प्रकार ऑनलाइन निगरानी प्रणाली ‘सुगम पथ’ और प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम (पीएमआईएस) के माध्यम से परियोजनाओं की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा रही है। वहीं, प्रदेश के 165 टोल प्लाजा पर फास्टैग सुविधा भी स्थापित की गई है, जिससे टोल भुगतान की प्रक्रिया अधिक सुगम हुई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सड़क विकास के नवाचारों से राजस्थान में बेहतर कनेक्टिविटी, सुरक्षित यातायात और आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण को गति मिल रही है।

सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के गांवों, कस्बों और शहरों को मजबूत सड़क नेटवर्क से जोड़ते हुए विकास को अंतिम छोर तक पहुंचाया जाए।

राइजिंग नीमराणा कार्यक्रम में राज्यपाल ने किया एनआईए भवन का लोकार्पण, एनआईए सर्किल, एनआईए लेन एवं पर्यावरण मार्ग का शिलान्यास

नीमराणा के औद्योगिक विकास में सरकार और उद्योग जगत की साझेदारी महत्वपूर्ण- राज्यपाल

जयपुर (कासं)। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने मंगलवार को राइजिंग नीमराणा कार्यक्रम के तहत नीमराणा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (एनआईए) के एनआईए/एमजी भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने एनआईए सर्किल, एनआईए लेन एवं पर्यावरण मार्ग का शिलान्यास भी किया। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने एनआईए के सभागार में क्षेत्र के उद्योगपतियों के साथ संवाद कर औद्योगिक विकास, सरकारी पहलों और नीमराणा की औद्योगिक महत्ता पर चर्चा की।

इस दौरान राज्यपाल बागडे ने औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों एवं पहलों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि उद्योग जगत प्रदेश की आर्थिक प्रगति और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नीमराणा जैसे प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र का राज्य की अर्थव्यवस्था में विशेष महत्व है। औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार के साथ आधारभूत सुविधाओं का विकास तथा सरकार और उद्योग जगत के बीच बेहतर समन्वय भी आवश्यक है। राज्यपाल बागडे ने उद्योग जगत के योगदान और औद्योगिक विकास की संभावनाओं के संदर्भ में नीमराणा की



भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि एनआईए भवन की पहल एसोसिएशन की गतिविधियों के संचालन और क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए 30 मोटरसाइकिलों को दिखाई झंडी

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने राजस्थान पुलिस के लिए 30 मोटरसाइकिलों को दिखाई झंडी

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने मंगलवार को कोटपूतली-बहरोड़ जिले के नीमराणा स्थित हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड के संयंत्र में राजस्थान पुलिस के लिए 30 मोटरसाइकिलों के अंतर्गत संचालित ‘राइड सेफ इंडिया’ कार्यक्रम के तहत राजस्थान पुलिस को मोटरसाइकिलें उपलब्ध कराने की पहल की सराहना की। राज्यपाल ने

सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों की पालना के प्रति जागरूकता बढ़ाने का संदेश दिया। बागडे ने हीरो मोटोकॉर्प की ओर से सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत संचालित ‘राइड सेफ इंडिया’ कार्यक्रम के तहत राजस्थान पुलिस को मोटरसाइकिलें उपलब्ध कराने की पहल की सराहना की। राज्यपाल ने



सुरक्षित वाहन संचालन को सड़क सुरक्षा का महत्वपूर्ण आधार बताते हुए यातायात नियमों की पालना के प्रति सजग रहने का संदेश दिया। उन्होंने इस प्रकार की पहलों को सड़क सुरक्षा के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने और यातायात व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण बताया। हीरो मोटोकॉर्प की ओर से राजस्थान

पुलिस को हेलमेट सहित प्रदान की गई 30मोटरसाइकिलों से पुलिस की गश्त व्यवस्था, यातायात प्रबंधन तथा आपात स्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इन वाहनों से पुलिस को अपने दायित्वों के निर्वहन में अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करने में सहायता मिलेगी।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भागीरथ प्रयास

3,588 करोड़ रुपये के ईसरदा प्रोजेक्ट से दौसा और सवाईमाधोपुर के 6 बड़े कस्बों और 1250 से ज्यादा गांवों में पेयजल समस्या का स्थायी समाधान जल्द

91000 करोड़ रुपये लागत की संशोधित पार्वती कालीसिंध चम्बल लिंक परियोजना में 23312 करोड़ रुपये के 7 पेयजल कार्य प्रगति पर**प्रथम पैकेज पर अब तक 1,006 करोड़ रुपये खर्च**

जयपुर (कासं)। दौसा और सवाई माधोपुर जिले के समग्र विकास में सबसे बड़ी बाधा पानी की कमी रही है। अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विकसित राजस्थानञ्च2047 का संकल्प पूरा करने में जल का महत्व समझते हुए इन दो जिलों के साथ ही सम्पूर्ण राज्य में पानी की समस्या के स्थायी समाधान के लिए संशोधित पार्वती कालीसिंध चम्बल लिंक परियोजना, किशौड बहुउद्देशीय बांध परियोजना, यमुना जल समझौते, देवास के अगले चरणों आदि के माध्यम से बड़े कदम उठाए, बरसों से लम्बित अन्तर्राज्यीय विवादों का समाधान किया और घोषणाओं के समय ही पूरे बजट का इंजाजाम भी किया जिससे घोषणाएं डेडलाइन पर नहीं, उससे पहले ही धरातल पर विकास की गंगा ला सके। डबल इंजन सरकार 91000 करोड़ रुपये की संशोधित पार्वती कालीसिंध चम्बल लिंक परियोजना

से इन दोनों जिलों के साथ ही पूरे पूर्वी राजस्थान में पानी की समस्या का स्थायी समाधान करने जा रही है। इससे खेती, उद्योग के साथ ही पेयजल के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध होगा। इस बजट में से 23312 करोड़ रुपये के 7 पेयजल कार्य प्रगति पर हैं। ईसरदा बांध के पानी को उपचारित कर गांवों और कस्बों तक पहुंचाने वाली ईसरदा-दौसा पेयजल परियोजना अब महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच गई है। करीब 3,588 करोड़ रुपये की इस महत्वाकांक्षीपरियोजना से 1,256 गांवों और 6 कस्बों को पेयजल नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। इसमें 3 लाख 6 हजार 198 से अधिक घरों तक नल से पेयजल कनेक्शन करने का लक्ष्य है, जिससे करीब 35 लाख लोगों को स्वच्छ एवं गुणवत्तापूर्ण पेयजल मिलेगा।

बांध से फिल्टर प्लांट तक पहुंचा पानी

परियोजना के अंतर्गत 225 एमएलडी क्षमता का फिल्टर प्लांट तैयार किया जा रहा है। अभी प्लांट की टेस्टिंग और कमिशनिंग का कार्य चल रहा है। ईसरदा बांध स्थित इंटेक वेल से पानी फिल्टर प्लांट तक पहुंचाया जा चुका है। प्रथम



341 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन में 299 किलोमीटर पूरा

परियोजना के प्रथम पैकेज में ईसरदा इंटेक वेल से मुहड़ा तक 341 किलोमीटर मुख्य ट्रांसमिशन प्रस्तावित पाइपलाइन में से 299 किलोमीटर बिछाई जा चुकी है। ईसरदा और बागड़ी में स्वच्छ जलाशयों तथा फिल्टर प्लांट का निर्माण भी पूरा हो चुका है। प्रथम



पैकेज पर अब तक 1,006 करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके हैं। ईसरदा बांध पर इंटेक वेल एवं पंप हाउस भवन निर्माण भी पूरा हो चुका है। यह कार्य द्वितीय पैकेज के तहत कराया गया है।

क्लस्टरों में आगे बढ़ रहा पेयजल नेटवर्क- लालसोट क्लस्टर में 302 गांवों और लालसोट शहर को लाभान्वित किया



जाना प्रस्तावित है। यहां 124.7 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है तथा 11 उच्च जलाशयों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। दौसा क्लस्टर में 248 गांवों एवं दौसा शहर को नेटवर्क से जोड़ने के लिए 1,709 किलोमीटर पाइपलाइन प्रस्तावित है। इसमें से 154 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है। 52 उच्च जलाशयों में से 11 तथा

9 स्वच्छ जलाशयों में से 2 का निर्माण चल रहा है। बसवा क्लस्टर में 368 गांवों और बांदीकुई शहर को लाभ मिलेगा। यहां प्रस्तावित 2,077 किलोमीटर पाइपलाइन में से 1,801 किलोमीटर का कार्य पूरा हो चुका है। इस पैकेज पर अब तक 217.17 करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके हैं। इसी प्रकार मुहड़ा क्लस्टर में प्रस्तावित 315 किलोमीटर

पाइपलाइन में से 244 किलोमीटर बिछाई जा चुकी है और इस कार्य पर 60.74 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

सवाई माधोपुर के 177 गांव भी जुड़ेंगे

परियोजना का विस्तार सवाई माधोपुर जिले तक भी किया जा रहा है। छठे पैकेज में बाँली तहसील के 99, मलारना डूंगर के 61 तथा चौथ का बरवाड़ा के 17 गांवों सहित कुल 177 गांवों को पेयजल सुविधा से लाभान्वित किया जाना है। इसके लिए 260.62 करोड़ रुपये का कार्यादेश जारी हो चुका है।

नवंबर तक शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति का लक्ष्य

परियोजना के शेष कार्यों को प्राथमिकता के साथ गति दी जा रही है। नवंबर तक शहरी क्षेत्रों को मुख्य पाइपलाइन के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने का प्रस्तावित लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही जिन ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक जल संरचनाओं का निर्माण पूरा हो चुका है, वहां चरणबद्ध रूप से पेयजल नेटवर्क से कनेक्शन जोड़कर जलापूर्ति शुरू की जाएगी।

पौषक तत्वों से परिपूर्ण है



चुकंदर

चुकंदर का रस पीने से न केवल शरीर में रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ती है बल्कि कई अन्य स्वास्थ्य लाभ भी होते हैं। यदि आप इस सब्जी से नफ़्त करते हैं तो ज़रा एक बार इसके फायदों के बारे में ज़रूर पढ़ लें। शायद कम लोग ही जानते हैं कि चुकंदर में लौह तत्व की मात्रा अधिक नहीं होती है, किंतु इससे प्राप्त होने वाला लौह तत्व उच्च गुणवत्ता का होता है, जो रक्त निर्माण के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि चुकंदर का सेवन शरीर से अनेक हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने में बेहद लाभदायी है। ऐसा समझा जाता है कि चुकंदर का गहरा लाल रंग इसमें लौह तत्व की प्रचुरता के कारण है, बल्कि सच यह है कि चुकंदर का गहरा लाल रंग इसमें पाए जाने वाले एक रंगकण (बीटा सायनिन) के कारण होता है। एंटी ऑक्सीडेंट गुणों के कारण ये रंगकण स्वास्थ्य के लिए अच्छे माने जाते हैं।

यदि आपको आलस महसूस हो रही हो या फिर थकान लगे तो चुकंदर का जूस पी लीजिये। इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है जो शरीर यह पानी फोड़े, जलन और मुहांसों के लिए काफी उपयोगी होता है। खसरा और बुखार में भी त्वचा को साफ करने में इसका उपयोग किया जा सकता है।

जो लोग जिम में जी तोड़ कर वर्कआउट करते हैं उनके लिये चुकंदर का जूस बहुत फायदेमंद है। इसको पीने से शरीर में एनर्जी बढ़ती है और थकान दूर होती है। साथ ही अगर हाई बीपी हो गया हो तो इसे पीने से केवल 1 घंटे में शरीर नार्मल हो जाता।

खराब नाखूनों का एक कारण यह भी है

कि उसे समय समय पर काट नहीं जाता। बाहर के वातावरण में सबसे पहले हमारे हाथ ही आगे आते हैं और जल्दी गंदे होते हैं इसलिए न केवल नाखून को ऊपर से ही बल्कि अंदर से भी साफ करना चाहिए। इसके लिए आपको गरम पानी और साबुन के घोल में डूबोने की ज़रूरत है और फिर उसे स्क्रब करने से हाथों की सफाई हो जाएगी। आपको सुंदर बनाने में आपकी त्वचा का सुंदर होना बहुत ज़रूरी है। आकर्षक स्किन हर लड़की की चाह होती है।



पार्टी के लिए जब लड़कियां नाखूनों की करती हैं

सजावट

न्यूयियर पार्टी के लिए जब लड़कियां तैयार होती हैं तो वह अपने नाखूनों की सजावट पर बहुत ध्यान देती हैं। इस से मैच करती हुई नेल पॉलिश लगाना तथा नेल आर्ट से नाखूनों को नया लुक देना बिल्कुल आम बात हो गई है। पर यह जान लेना बहुत ही ज़रूरी है कि नाखून पर कोई भी सजावट तभी अच्छी लगती है जब वह बिल्कुल स्वस्थ हों। आइये जानते हैं नाखूनों को हैल्दी रखने के टिप्स। सबसे अहम बात यह कि आपका खाना ही आपके नाखूनों की सही पहचान है। अच्छे नाखूनों के लिए आपकी डाइट में कैल्शियम की मात्रा अधिक होनी चाहिए।



नेल पॉलिश को नहीं लगाएं

सबसे पहला कदम यह अपनाएं कि नाखूनों पर एक हफ्ते से ज्यादा देर के लिए नेल पॉलिश को न लगा रहने दें। अगर नेल पॉलिश ज्यादा समय के लिए नाखून पर रहती है तो वह नाखूनों की सतह को खराब बना देती है। साथ ही नाखून बदरंग और अस्वस्थ हो जाते हैं।

क्यूटिकल्स को साफ रखें

क्यूटिकल्स नाखूनों के दोनों ओर होते हैं जिसमें गंदगी जब जाती है। यह इतने प्रभावशाली होते हैं कि इसकी वजह से नाखून सड़ भी जाते हैं। अच्छा होगा की आप समय समय पर क्यूटिकल्स को काटती रहें। अपने नाखूनों को चमकदार और स्वस्थ बना के लिए उसकी हमेशा नारियल और अरंडी तेल से मसाज करती रहें। नाखूनों को शेप देते समय उन्हें एक ही दिशा में लें जाएं। जगह-जगह से शेप देने की वजह से उनकी क्वालिटी खराब हो जाती है।

नींबू का रस

चेहरे पर इंस्टेंट ग्लो पाने के लिए बाहरी सौंदर्य प्रसाधनों की अपेक्षा घरेलू प्रसाधन ज्यादा, प्रभावकारी और लाभदायक होते हैं। जानते हैं- नींबू का रस त्वचा पर लगाने से स्यापन और सफेदी दूर होती है। सखी त्वचा पर ग्लिसरीन व नींबू जलूर लगाएं।



पपीते का मास्क

पपीते का मास्क बनाने के लिए पपीते का गुदा लें और उसमें दही मिलाकर चेहरे पर लगाने से इंस्टेंट ग्लो आता है।



खीरे और दही का मास्क

खीरे और दही के मास्क को बनाने के लिए 1/2 खीरे का रस और 1 चम्मच दही लें। फिर इन दोनों को आपस में मिलाकर 10 से 15 मिनट के लिए चेहरे पर लगा लें। फिर धो दें। इनसे आपके चेहरे पर चमक आएगी।

आड़ू का मास्क बनाने के लिए सबसे पहले तो आड़ू के गूदे को निकालकर उसे मैश कर लें, फिर उसमें शहद और दही मिलाकर लगाएं। इससे चेहरे पर तुरंत निखार आएगा। सबसे पहले तो केले को छीलकर गूदे को मैश कर लें, फिर उसमें 1 छोटा चम्मच शहद और 2 छोटा चम्मच दही मिलाएं। फिर उसे त्वचा पर लगाएं।

डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी मीट-2026 का शुभारम्भ

विद्युत वितरण निगमों को वित्तीय रूप से सुदृढ़, आधुनिक एवं उपभोक्ता-केन्द्रित बनाना सरकार की प्राथमिकता: नागर

एआई एवं नवीकरणीय ऊर्जा के प्रभावी एकीकरण पर जोर- मुख्य सचिव

जयपुर (कासं)। ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हिरालाल नागर ने कहा कि विद्युत वितरण निगमों को वित्तीय रूप से सुदृढ़, तकनीकी रूप से सक्षम एवं उपभोक्ता-केन्द्रित बनाना समय की आवश्यकता है। स्मार्ट मीटरिंग, डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) एवं ऑटोमेशन के प्रभावी उपयोग से विद्युत वितरण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, दक्ष और विश्वसनीय बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक उपभोक्ता को निर्बाध बिजली के साथ-साथ गुणवत्तापूर्ण विद्युत सेवाएं उपलब्ध हो सके। इसके लिए राज्य सरकार वितरण तंत्र के सुदृढ़ीकरण की दिशा में तेजी से काम कर रही है।

नागर मंगलवार को राज्य सरकार के ऊर्जा विभाग एवं इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम के संयुक्त तत्वावधान में जयपुर में विद्युत वितरण निगमों की 10वीं राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस 'डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी मीट-2026' के शुभारंभ सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा

कि राज्य सरकार की नीतियों से राजस्थान देश के प्रमुख सौर ऊर्जा केंद्र के रूप में उभरा है। प्रदेश की स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता लगभग 45 गीगावाट तथा कुल अक्षय ऊर्जा क्षमता लगभग 52 गीगावाट तक पहुंच गई है। पिछले तीन वर्षों से भी कम समय में अक्षय ऊर्जा क्षमता में लगभग 28 गीगावाट से अधिक की वृद्धि हुई है। यह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में एनर्जी सेक्टर को बढ़ावा देने के दूरदर्शी प्रयासों का ही परिणाम है।

नागर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पीएम सूर्यघर एवं प्रधानमंत्री कुसुम जैसी योजनाओं से सुदृढ़ीकरण की दिशा में तेजी से काम कर रही है। राजस्थान में पीएम सूर्यघर योजना में 3.55 लाख से अधिक घरों में रूफटॉप सोलर स्थापित किए जा चुके हैं। वहीं, कुसुम कम्पोनेंट-ए एवं कम्पोनेंट-सी के तहत लगभग 5,500 मेगावाट से अधिक की विकेन्द्रीकृत सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की जा चुकी हैं, जिनसे 3.75 लाख से अधिक किसानों

को दिन में कृषि कार्यों के लिए बिजली उपलब्ध हो रही है। इससे किसान अन्नदाता के साथ ऊर्जादाता भी बन रहे हैं। नागर ने कहा कि बिजली की बढ़ती मांग और नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार के बीच प्रदेश में बैटरी ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं को बढ़ावा देने, ग्रिड आधुनिकीकरण, एटीएंडसी हानियों में कमी के साथ ही डिस्कॉम के आर्थिक सशक्तीकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस दिशा में जयपुर डिस्कॉम ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में 931 करोड़ रूपए का लाभ अर्जित किया है जो वितरण निगमों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के हमारी इच्छाशक्ति को दर्शाता है।

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि इस आयोजन से देश भर के विद्युत वितरण निगमों को अपने बेस्ट प्रैक्टिसेज, नवाचारों तथा धरातल के सकारात्मक अनुभवों को परस्पर साझा करने का मंच मिला है। उन्होंने कहा कि भारत तेजी से वैश्विक आर्थिक ताकत के रूप में उभर रहा है। उस



अनुरूप देश में 'ऊर्जा की मांग में भी बढ़ाव' भी हो रही है। उन्होंने कहा कि विद्युत क्षेत्र सुधार 2.0 के तहत विद्युत वितरण निगम वित्तीय रूप से मजबूत बनाने की दिशा में आगे बढ़े हैं। अजमेर विद्युत वितरण निगम के बाद अब जयपुर डिस्कॉम की सारहना भी की। इससे पहले ऊर्जा विभाग की शासन सचिव सुआरती डोगरा ने स्वागत उद्घोषण में ऊर्जा क्षेत्र में सुधार, विद्युत वितरण व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने तथा आधुनिक तकनीक एवं नवीकरणीय ऊर्जा के बेहतर उपयोग के महत्व पर विचार रखे। इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम के प्रेसीडेंट रेजी कुमार पिल्लई ने कहा कि भारत की प्रगति के लिए वितरण निगमों का सशक्तीकरण आवश्यक है।

मुख्य सचिव ने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण के लिए राज्य में वितरण नेटवर्क को आधुनिक बनाया जा रहा है। उन्होंने बैटरी ऊर्जा भंडारण, मांग के सटीक पूर्वानुमान तथा परेषण एवं वितरण तंत्र के बीच समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया। मुख्य सचिव ने कहा कि उपभोक्ता सेवाओं को बेहतर बनाने की

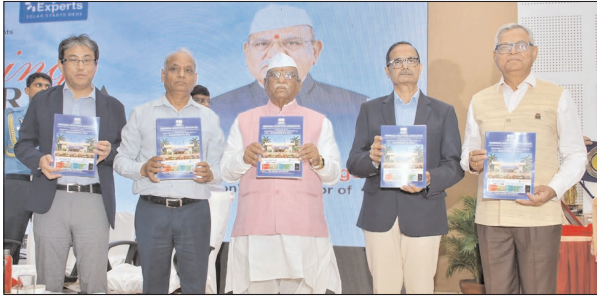
केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के चेयरपर्सन धनश्याम प्रसाद, एमपीसीएल के एमडी प्रेमकुमार, एआईडीए के महानिदेशक आलोक कुमार, पावर फाउंडेशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक आरके त्यागी, जीयूवीएनएल की एमडी शालिनी अग्रवाल तथा इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम की सीईओ रीना सूरी ने भी उद्घाटन सत्र को संबोधित किया।

दो दिवसीय इस राष्ट्रीय सम्मेलन में विद्युत वितरण क्षेत्र में वित्तीय परिवर्तन, डिजिटल इंटेलिजेंस, स्मार्ट मीटर के डेटा विश्लेषण, एआई टूल्स, साइबर सुरक्षा, ग्रिड आधुनिकीकरण, ऊर्जा भंडारण, शून्य कार्बन उत्सर्जन तथा डेटा सेंटरों एवं इलेक्ट्रिक वाहनों से बढ़ती बिजली मांग के प्रबंधन जैसे विषयों पर चर्चा की जा रही है।

सम्मेलन का उद्देश्य देशभर की विद्युत वितरण कंपनियों के श्रेष्ठ अनुभवों एवं कार्यप्रणालियों को साझा कर व्यावहारिक समाधान विकसित करना है। राजस्थान को पहली बार इस राष्ट्रीय आयोजन की मेजबानी का अवसर मिला है।

भारत-जापान सहयोग, आधुनिक विनिर्माण तकनीक और निवेश से औद्योगिक विकास को मिलेगी गति

'राइजिंग नीमराणा' में औद्योगिक विकास और निवेश विस्तार पर मंथन, राज्यपाल ने उद्योगों एवं संस्थाओं को किया सम्मानित



जयपुर (कासं)। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि औद्योगिक विकास के लिए आधुनिक तकनीक और निवेश को बढ़ावा देना आवश्यक है। राज्यपाल बागडे मंगलवार को कोटपूतली-बहरोड़ जिले के नीमराणा स्थित एनआईआईटी यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में नीमराणा इंडस्ट्री एसोसिएशन एवं रोज एक्सपर्ट के संयुक्त तत्वावधान में द टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा औद्योगिक विकास एवं निवेश संवर्धन की परिकल्पना के साथ आयोजित 'राइजिंग नीमराणा' कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल ने औद्योगिक विकास, निवेश विस्तार, भारत-जापान सहयोग तथा देश की आर्थिक प्रगति के विभिन्न पहलुओं पर विचार व्यक्त किए।

राज्यपाल बागडे ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार औद्योगिक विकास और निवेश संवर्धन को गति देने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में

आधुनिक विनिर्माण तकनीक को प्रोत्साहित करने तथा निवेश संबंधी योजनाओं को धरातल पर लागू करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नीमराणा निरंतर औद्योगिक क्षेत्र में अपनी पहचान मजबूत कर रहा है और वैश्विक औद्योगिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण स्थान की ओर अग्रसर है।

राज्यपाल ने भारत-जापान आर्थिक संबंधों का उल्लेख करते हुए कहा कि जापानी उद्योगों एवं निगमों को बढ़ावा देने, औद्योगिक साझेदारी को विस्तार देने तथा उत्पादों के आयात-निर्यात को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। आधुनिक तकनीक, निवेश

और पारस्परिक सहयोग के माध्यम से औद्योगिक क्षेत्र में नई संभावनाओं का सृजन किया जा सकता है। उन्होंने भारत में बुलेट ट्रेन सहित विभिन्न क्षेत्रों में जापान द्वारा दिए जा रहे सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने भारत और जापान के ऐतिहासिक संबंधों तथा दोनों देशों की संघर्ष और विकास यात्रा का उल्लेख करते हुए आर्थिक प्रगति, तकनीकी नवाचार और औद्योगिक विस्तार में आपसी सहयोग के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने भारतीय इतिहास, संस्कृति, नैतिक मूल्यों, समृद्ध परंपराओं और शिक्षा को देश की महत्वपूर्ण

धरोहर बताते हुए इनके संरक्षण एवं संवर्धन पर बल दिया। उन्होंने सभी से समन्वय और सहयोग के साथ विकास की राह पर आगे बढ़ने तथा राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए 'देश प्रथम' की भावना के साथ कार्य करने का आह्वान किया।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने नीमराणा एवं कोटपूतली-बहरोड़ जिले के औद्योगिक विकास में उल्लेखनीय योगदान देने वाले उद्योगों, संस्थाओं एवं विशिष्ट व्यक्तित्वों को विभिन्न श्रेणियों में सम्मानित किया। सम्मान समारोह में नीमराणा में स्थापित शुरुआती उद्योगों, जापानी औद्योगिक क्षेत्र के प्रार्थिक उद्योगों, रोजगार सृजन, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण, पर्यटन एवं विरासत संरक्षण तथा औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले उद्योगों एवं संस्थाओं को सम्मान प्रदान किए गए। इस अवसर पर राज्यपाल ने 'नीमराणा दर्पण' पुस्तिका का विमोचन भी किया।

दीपावली के मद्देनजर 'शुद्ध आहार-मिलावट पर वार' अभियान में तेजी लाएं- गायत्री राठौड़



जयपुर (कासं)। प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्रीमती गायत्री राठौड़ ने दीपावली के त्योहारी सीजन को देखते हुए प्रदेश में 'शुद्ध आहार-मिलावट पर वार' अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आमजन के स्वास्थ्य की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। खाद्य पदार्थों में मिलावट कर लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कार्रवाई पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ हो तथा किसी भी प्रकार के दबाव या दुर्भावना में कार्रवाई नहीं की जाए।

श्रीमती राठौड़ ने मंगलवार को स्वास्थ्य भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित समीक्षा बैठक में प्रदेश की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं और विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांच के दौरान विनिर्माण इकाइयों पर विशेष ध्यान देने के साथ उन बाजारों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों

पर भी फोकस करने के निर्देश दिए, जहां से आमजन खाद्य सामग्री खरीदते हैं। श्रीमती राठौड़ ने सिलीकोसिस रोगियों से संबंधित लंबित प्रकरणों का 31 अक्टूबर तक निस्तारण करने तथा जानबूझकर लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत नॉट मशीनों का निर्धारित उपयोग सुनिश्चित करने, चयनित टीबी रोगियों को निर्यात पोषण किट उपलब्ध करवाने और निक्षय पोर्टल पर जानकारी समय पर अपलोड करने के निर्देश दिए।

साथ ही, स्क्रब टाइफस सहित मौसमी बीमारियों की रोकथाम और निगरानी प्रभावी बनाने को कहा। विदेश से आने वाले इबोला के संभावित यात्रियों के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार आवश्यक निगरानी एवं आइसोलेशन की व्यवस्था करने तथा कम से कम 21 दिनों तक निगरानी रखने के निर्देश भी दिए।

जयपुर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई, 7 केंटर सामान जब्त

जयपुर (कासं)। नगर निगम जयपुर आयुक्त ओम कसेरा के निर्देशानुसार एवं पूर्व से प्राप्त शिकायतों पर उपायुक्त सतर्कता के नेतृत्व में मंगलवार को सतर्कता शाखा की द्वारा नगर निगम जयपुर क्षेत्राधिकार में नकुलपथ लालकोठी स्क्रीम, टॉक फाटक बरकत नगर, मधुवन कॉलोनी किसान मार्ग, दुर्गापुर पुलिस के नीचे, श्योपुर रोड़, एनआरआई सर्किल, जूडियों मालवीय नगर, एनएनआईटी कॉलेज केलगिरी रोड़, बैनाड़ रोड़, सीतावाली फाटक, निवारू रोड़ वैद्य जी का चैराहा, मेडिकल सेंटर कालवाड़ रोड़, विद्याधर नगर आदि स्थानों से आदि अस्थाई अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध 38 हजार रुपये का कैरिंग चार्ज वसूल कर 7 केन्टर सामान जब्त किया गया। उपायुक्त सतर्कता ने बताया कि नगर निगम जयपुर क्षेत्राधिकार में नकुलपथ लालकोठी स्क्रीम, टॉक फाटक बरकत नगर, मधुवन कॉलोनी किसान मार्ग, दुर्गापुर पुलिस के नीचे, श्योपुर रोड़, एनआरआई सर्किल, जूडियों मालवीय नगर, एनएनआईटी कॉलेज केलगिरी रोड़, बैनाड़ रोड़, सीतावाली फाटक, निवारू रोड़ वैद्य जी का चैराहा, मेडिकल सेंटर कालवाड़ रोड़, विद्याधर नगर आदि स्थानों से अस्थाई अतिक्रमण को हटवाया गया। तत्काल कार्रवाई के दौरान 7 केन्टर सामान जब्त कर गोदाम में भिजवाया गया व अस्थाई अतिक्रमण करने वालों से मौके पर 38 हजार रुपये का कैरिंग चार्ज वसूल किया गया। तथा दौरे के दौरान कार्यवाही सतर्कता टीम द्वारा मौके पर समझाइश करते हुए मौखिक पाबंद करवाया कि भविष्य में अस्थाई अतिक्रमण समय से हटा ले अन्यथा नगर निगम जयपुर के क्षेत्राधिकार में अवैध अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध भारी कार्रवाई चालान या प्रभावी कार्रवाई अमल में लाई जायेगी।

खनन प्रभावित क्षेत्रों में डीएमएफटी फण्ड को जिला कलेक्टर बनाएं विकास का माध्यम- श्रीनिवास

प्राथमिकता क्षेत्रों पर करें फोकस, गुणवत्ता और कार्यपूरुता पर जोर

जयपुर (कासं)। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन फण्ड से प्राथमिकता क्षेत्र के कार्यों पर विशेष जोर देते हुए खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास का प्रमुख माध्यम बनाएं। उन्होंने कहा कि पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, युवाओं व महिलाओं के कौशल विकास सहित प्राथमिकता वाले क्षेत्र के कार्यों पर फोकस करने के साथ ही कार्यों की गुणवत्ता और पूर्णता पर ध्यान देना होगा। उन्होंने वित्त विभाग को निर्देश दिए कि कार्यों की गुणवत्ता और प्राथमिकता देखते हुए राशि स्वीकृत करें और प्रभावी मॉनीटरिंग तय की जाए।

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास सचिवालय में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन की राज्य स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि डीएमएफटी फण्ड के गुणवत्तापूर्ण और बेहतर उपयोग के लिए कलेक्टर स्तर पर डीएमएफटी संचालन समितियों को नियतकालीन बैठकें आयोजित करने, क्षेत्र की आवश्यकताओं को चिन्हित करने और विकास परक कार्यों की स्वीकृति और प्रभावी मॉनेटरिंग व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव माईस श्रीमती अर्पणा अरोरा ने बताया कि डीएमएफटी से खनन प्रभावित क्षेत्रवासियों को पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, पर्यावरण विकास सहित प्राथमिकता क्षेत्र के कार्य करने के साथ ही 30 प्रतिशत राशि से सड़क, आधारभूत संरचना आदि कार्य कराने के प्रधान है। डीएमएफटी फण्ड से संबंधित जिलों में अब तक 12311 करोड़ 15 लाख रुपए की राशि के कार्य स्वीकृत किये जा चुके हैं जिसमें से 7217 करोड़ 28 लाख रुपए व्यय हो चुके हैं।

श्रीमती अर्पणा अरोरा ने कहा कि जिला कलेक्टरों को खनन क्षेत्रों के डीएमएफटी से कार्य स्वीकृत करते समय प्राथमिकता तय करनी होगी ताकि इस राशि से खनन क्षेत्रों से प्रभावित गांवों में विकास और लोगों को आधारभूत सुविधाएं मिल सकें। अतिरिक्त मुख्य सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग प्रवीण गुप्ता, प्रमुख सचिव मेडिकल श्रीमती गायत्री राठौड़, प्रमुख सचिव पीएचईडी हेमंत गैरा, सचिव वित्त श्रीमती टीना सोनी ने डीएमएफटी में उपलब्ध राशि के उपयोग पर संतोष व्यक्त करते हुए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। साथ ही, विशिष्ट सचिव माईस श्रीमती नम्रता वृष्णि ने डीएमएफटी के कार्यों और प्रगति की विस्तार से जानकारी दी।

पृथ्वीराज मील समर्थकों सहित भाजपा में शामिल



जयपुर (कासं)। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने श्रीगंगानगर के पूर्व जिला प्रमुख पृथ्वीराज मील और उनके दर्जनभर से अधिक समर्थकों को पार्टी का दुपट्टा पहनाकर सदस्यता ग्रहण करवाई।

राठौड़ ने कहा कि पृथ्वीराज मील सहित समाज के जागरूक लोगों का भाजपा के साथ जुड़ना संगठन के लिए उत्साहजनक है। इससे पार्टी की ताकत बढ़ेगी और राष्ट्रीय नेतृत्व को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को विकसित भारत बनाने के लिए जो संकल्प लिया गया है, उसे पूरा करने में समाज के प्रत्येक वर्ग का योगदान महत्वपूर्ण है।

ऐसे समय में समाज के प्रतिनिधियों का भाजपा के साथ आना संगठन के लिए गौरव और प्रसन्नता का विषय है। इस दौरान भाजपा प्रदेश

प्रभारी संजय भाटिया, प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने पार्टी ग्रहण करने वाले सभी कार्यकर्ताओं का हार्दिक अभिनंदन किया।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि पृथ्वीराज मील ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के साथ ही पंजाब विधानसभा चुनाव में भाजपा को मजबूत बनाने के लिए पूर्ण उत्साहजनक है। इससे पार्टी की ताकत बढ़ेगी और राष्ट्रीय नेतृत्व को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को विकसित भारत बनाने के लिए जो संकल्प लिया गया है, उसे पूरा करने में समाज के प्रत्येक वर्ग का योगदान महत्वपूर्ण है। ऐसे समय में समाज के प्रतिनिधियों का भाजपा के साथ आना संगठन के लिए गौरव और प्रसन्नता का विषय है। इस दौरान भाजपा प्रदेश

लोगों के सहयोग से राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार को भी मजबूती मिलेगी। राजस्थान में पंचायत चुनाव हो या पंजाब में विधानसभा चुनाव, समाज के प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी और उनकी संगठनात्मक क्षमता पार्टी के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। उन्होंने सभी उपस्थित प्रतिनिधियों, कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों का स्वागत, अभिनंदन और सीमा से जुड़े क्षेत्रों के लोगों के बीच भाषाई एवं सामाजिक समानताएं होने पर भाजपा की जीत के लिए अपनी पूरी टीम के साथ योगदान देने का संकल्प स्वागतयोग्य है। उन्होंने कहा कि समाज के प्रतिनिधि अपनी संगठनात्मक क्षमता और जनसंपर्क के माध्यम से भाजपा को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। समाज के

न्यूज़ इनबॉक्स

मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजनान्तर्गत ऑनलाईन आवेदन अब 5 नवम्बर तक किये जा सकेंगे

जयपुर (कासं)। राज्य में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री कोचिंग योजनान्तर्गत विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स एवं सरकारी नौकरियों के लिए आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं की उत्कृष्ट तैयारी एवं समान अवसर प्रदान करने के लिए विभाग द्वारा ऑनलाईन पोर्टल पर सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों में निःशुल्क कोचिंग करने हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों से वर्ष 2026-27 के लिए ऑनलाईन आवेदन की अंतिम दिनांक 05 नवम्बर 2026 निर्धारित कर दी गई है। ललित कुमार, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने बताया कि योजनान्तर्गत विभाग द्वारा निःशुल्क कोचिंग करने हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों के हित में उपरोक्त संशोधन किया गया है जिससे जरूरतमन्द अभ्यर्थियों को अधिकाधिक लाभान्वित किया जा सके। पूर्व में वर्ष 2026-27 के लिए पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन करने हेतु अंतिम दिनांक 25 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई थी जिसे अब अंतिम दिनांक 05 नवम्बर 2026 तक बढ़ा दिया गया है।

14-15 वर्ष आयुवर्ग की किशोरियों को लगाई एचपीवी वैक्सीन

जयपुर (कासं)। सुरक्षित मातृत्व अभियान के अंतर्गत मंगलवार को जिले के स्वास्थ्य संस्थानों पर गर्भवती महिलाओं की सघन प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जांच (एनएस) आयोजित की गई। अभियान के दौरान विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा गर्भवती महिलाओं की विस्तृत जांच कर हाई रिस्क प्रेनेंसी (एचआरपी) की समय पर पहचान की गई तथा आवश्यक उपचार, परामर्श एवं नियमित फॉलोअप सुनिश्चित किया गया। सीएमएचओ जयपुर द्वितीय डॉ. मनीष मित्तल ने बताया कि सुरक्षित मातृत्व अभियान का उद्देश्य प्रत्येक गर्भवती महिला को गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना तथा हाई रिस्क गर्भावस्था की समय रहते पहचान कर जटिलताओं से बचाव करना है। अभियान के दौरान चिन्हित हाई रिस्क गर्भवतियों को विशेषज्ञ चिकित्सकों की निगरानी में उपचार उपलब्ध कराया गया। इसके साथ ही 14-15 वर्ष आयुवर्ग की किशोरियों को एचपीवी वैक्सीन लगाई गई। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत पात्र महिलाओं को मां वाउचर योजना के अंतर्गत सोनोग्राफी वाउचर वितरित किए गए। वहीं एनीमिया से पीड़ित गर्भवती महिलाओं को फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज (एफसीएम) इंजेक्शन लगाए गए, जिससे रक्त की कमी को शीघ्र दूर कर सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित किया जा सके।

तीन रेलगाड़ियों के संचालन समय में आंशिक परिवर्तन

जयपुर (कासं)। रेलवे द्वारा परिचालन सुगमता के मद्देनजर तीन रेलगाड़ियों के संचालन समय में आंशिक परिवर्तन किया जा रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन के अनुसार गाड़ी संख्या 19604, गोंडा-दौराई एक्सप्रेस रेलसेवा: 05 जनवरी 2027 से गोंडा से प्रस्थान करने वाली इस रेलसेवा के मार्ग में आने वाले गाजियाबाद, दिल्ली, गुरुग्राम, रेवाड़ी, अटेली एवं नारनौल स्टेशनों पर संचालन समय में आंशिक परिवर्तन किया जा रहा है। गाड़ी संख्या 12556, बडिंडा-गोरखपुर एक्सप्रेस रेलसेवा: 28 अक्टूबर 2026 से इस रेलसेवा का कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर परिवर्तित समयानुसार आगमन रात्रि 03:00 बजे तथा प्रस्थान 03:10 बजे होगा। गाड़ी संख्या 54085, दिल्ली-सातरोड़ रेलसेवा: 28 अक्टूबर 2026 से इस रेलसेवा का दिल्ली स्टेशन से प्रस्थान परिवर्तित समयानुसार प्रातः 06:35 बजे होगा। इसके साथ ही, मार्ग में आने वाले दिल्ली साराय रोहिल्ला, दिल्ली नगर, दिल्ली कैंट, पालम, शाहबाद मोहम्मदपुर, बिजवासन, गुरुग्राम, बसई धनकोट, गढ़ी हरसरू, पातली, ताज नगर, जटौला जोड़ी सांपका, पटौदी रोड़, इछपुरी, खलीलपुर, कुम्भावास मुंढलिया डाबड़ी, रेवाड़ी, जटुसना, कोसली, झाड़ली, पाटुवास महराना, चरखी दादरी, भिवानी, भवानी खेड़ा एवं सातरोड़ स्टेशनों पर संचालन समय में आंशिक परिवर्तन किया जा रहा है।

सांतरागाछी-खातीपुरा-सांतरागाछी साप्ताहिक नई

रेलसेवा का नियमित संचालन

जयपुर (कासं)। रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए सांतरागाछी-खातीपुरा (जयपुर)-सांतरागाछी साप्ताहिक नई रेलसेवा का संचालन किया जा रहा है। इस रेलसेवा का नियमित संचालन सांतरागाछी से 4 नवंबर, 2026 तथा खातीपुरा (जयपुर) से 6 नवंबर, 2026 से प्रारंभ होगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन के अनुसार, गाड़ी संख्या 18061, सांतरागाछी-खातीपुरा साप्ताहिक रेलसेवा 4 नवंबर, 2026 (बुधवार) से प्रत्येक बुधवार को सांतरागाछी से 14.15 बजे खाना होकर अगले दिन गुरुवार को 23.00 बजे खातीपुरा पहुंचेगी। इसी प्रकार, गाड़ी संख्या 18062, खातीपुरा-सांतरागाछी साप्ताहिक रेलसेवा 6 नवंबर, 2026 (शुक्रवार) से प्रत्येक शुक्रवार को खातीपुरा से 09.15 बजे खाना होकर अगले दिन शनिवार को 19.45 बजे सांतरागाछी पहुंचेगी।

खातीपुरा से शालीमार एवं टाटानगर के लिए एकतरफा स्पेशल रेलसेवाओं का संचालन

जयपुर (कासं)। रेलवे द्वारा त्योहारों के अवसर पर अतिरिक्त यात्री यातायात को देखते हुए यात्रियों की सुविधा हेतु खातीपुरा से शालीमार एवं टाटानगर के लिए एकतरफा स्पेशल रेलसेवाओं का संचालन किया जा रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन के अनुसार गाड़ी संख्या 08062, खातीपुरा-शालीमार एकतरफा स्पेशल रेलसेवा 28 अक्टूबर 2026, बुधवार को खातीपुरा से 07.40 बजे खाना होकर अगले दिन 19.00 बजे शालीमार पहुंचेगी। यह रेलसेवा मार्ग में दीसा, बांड़ीकुई, मंडावर महवा रोड़, खेड़ली, ईदगाहा आगरा जंक्शन, टूंडला जंक्शन, कानपुर सेंट्रल, फतेहपुर, प्रयागराज जंक्शन, मिर्जापुर, पं. दीनदयाल उपाध्याय, भधुआ रोड़, सासाराम, डेहरी आन सोन, जपला, गढ़वा रोड़, डाल्टनगंज, बरवाडीह, लातेहार, रांची, लोहरदगा, रांची, मुरी, पुरुलिया, चाँडिल, टाटानगर, खड़गपुर एवं सांतरागाछी स्टेशनों पर हटाव करेगी। इस स्पेशल रेलसेवा में 01 सेकंड एसी, 04 थर्ड एसी, 06 द्वितीय शयनयान, 04 साधारण श्रेणी, 01 पावरकार, 01 पेंट्रीकार एवं 01 गाई डिब्बे सहित कुल 18 डिब्बे होंगे।

Municipal Corporation, Bhilwara (Raj.)
Email. ID : npbhlwara@gmail.com Contact No. 01482-232651, 652
क्रमांक: न.नि.भी./निर्माण/2026-27/14436 दिनांक: 23.10.2026
:: Notice Inviting Bid ::
Bid for Municipal Corporation Bhilwara For Online Tender 19/2026-27 Date 22.10.2026 (Preparation of the Detailed Project Report (DPR) for River Front development work along the banks of the Kothari River within the Municipal area. (CM Budget Announcement No. 32.27.00/2026-27(Re-Tender))Invited form interested bidders Date 16.11.2026 Upto 6.00 P.M. Other particulars of the bid may be invited on the procurement portal. (http://sppp.raj.nic.in) of the state.
NIB CODE :-DLB2627A9098
UBN CODE :-DLB2627WSOB23042
Executive Engineer
Nagar Nigam Bhilwara
Raj,Samwadd/C/261/2559